

## हरियाणा में पाॅक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट

### चर्चा में क्यों?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा को पाॅक्सो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये दो महीने के भीतर फरीदाबाद, पंचकूला और गुरुग्राम में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचति करने का नरिदेश दिया है।

### मुख्य बदि

- अतरिक्त न्यायालयों का गठन:
  - यह नरिदेश पाॅक्सो अधिनियम के तहत अपराधों से नपिटने के लिये अतरिक्त न्यायालयों के गठन की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान जारी कया गया।
  - याचिका में स्वतः संज्ञान मामले में जारी सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेशों को लागू करने की भी मांग की गई है।
  - भारत के सॉलसिटर जनरल के अनुसार, केंद्र सरकार ने देश भर में फास्ट ट्रैक और पाॅक्सो न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिये 200 करोड़ रुपए आवंटति कये थे।
- पाॅक्सो अधिनियम के बारे में:
  - इस कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन दुरव्यवहार के अपराधों को संबोधति करना है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के कसी भी व्यक्त को बच्चे के रूप में परभाषति करता है।
  - इसे वर्ष 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमति कया गया था।
- वशिषताएँ:
  - लगि-तटस्थ प्रकृति: अधिनियम यह मानता है क लडकयिँ और लडके दोनों यौन शोषण के शकार हो सकते हैं और ऐसा दुरव्यवहार अपराध है, चाहे पीडति का लगि कुछ भी हो।
  - पीडति की पहचान की गोपनीयता: POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 23 के अनुसार बाल पीडतियों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहयि। मीडिया रिपोर्ट में पीडति की पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती, जसिमें उनका नाम, पता और परिवार की जानकारी शामिल है।
  - बाल दुरव्यवहार के मामलों की अनवार्य रिपोर्टगि: धारा 19 से 22 ऐसे व्यक्तियों को, जनिहें ऐसे अपराधों की जानकारी है या उचति संदेह है, संबधति प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिये बाध्य करती है।

### भारत के सॉलसिटर जनरल (SGI)

- यह भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सर्वोच्च वधि अधिकारी है।
- यह कोई संवैधानिक पद नहीं है बलक वैधानिक नियमों द्वारा शासति है।
- वधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 के अनुसार इसका मुख्यालय नई दल्लि में होगा।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नयुक्त समति (ACC) द्वारा नयुक्त कया जाता है।
- इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।
- इसके कर्तव्यों में सरकार को सलाह देना, अदालतों में उपस्थति होना और अनुच्छेद 143 के संदर्भों को संभालना शामिल है।
- बना अनुमति के सरकार के खिलाफ पेश नहीं हो सकते या आपराधिक आरोपी का बचाव नहीं कर सकते।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मंत्रालयों को सीधे सलाह नहीं दी जा सकती; इसके लिये कानूनी मामलों के वभिग से परामर्श लेना होगा।
- नरिदषित सार्वजनिक या सरकार-नयित्त्रति संस्थाओं को छोड़कर नजी प्रैक्टिस पर प्रतबिंध है।
- बना पूर्व सरकारी अनुमोदन के लाभकारी पद पर नहीं रह सकते।

